हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 290 : जौनपुर, शनिवार 22 जुलाई 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य : 2 रूपया

प्रौद्योगिकी होगी रोजगार का मुख्य आधार : पीएम मोदी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। जी20 श्रम मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यह चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है, जहां प्रौद्योगिकी रोजगार के लिए मुख्य चालक बन गई है और रहेगी। इंदौर में आयोजित बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, श्स्किलिंग, री–स्किलिंग और अप–स्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र हैं। भारत में दुनिया में कुशल कार्यबल के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है। हमें प्रत्येक देश की अद्वितीय आर्थिक क्षमताओं, शक्तियों और चुनौतियों पर विचार करना चाहिए।

एक आकार–सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाना सामाजिक सुरक्षा के स्थायी वित्तपोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रधान मंत्री ने पिछले ऐसे प्रौद्योगिकी–आधारित परिवर्तन के दौरान अनगिनत प्रौद्योगिकी नौकरियां पैदा करने में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विकास के वैश्वीकरण और कौशल को सही अर्थों में साझा करने में जी20 की भूमिका पर भी जोर दिया। मोदी ने कौशल और योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को शुरू करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के नए मॉडल और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने शुरुआत के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के संबंध में आंकड़े, सूचना और डेटा साझा करने का सुझाव दिया, जो दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल, कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार के लिए साक्ष्य–आधारित नीतियां बनाने के लिए सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि भले ही लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना 2030 एजेंडा का एक प्रमुख पहलू है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई गई वर्तमान रूपरेखा केवल उन लाभों के लिए है, जो कुछ संकीर्ण तरीकों से संरचित हैं, जबकि अन्य रूपों में प्रदान किए गए कई लाभ इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं। मोदी ने रेखांकित किया कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सही तस्वीर समझने के लिए, सार्वभौमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बीमा और पेंशन कार्यक्रमों जैसे लाभों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मणिपुर की घटना पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष गंभीर नहीं : राजनाथ

एजेन्सी

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि मणिपुर की घटना पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं दिखाई पड़ता है। लोकसभा में मणिपुर के विषय पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार का पक्ष रखते हुए सदन के उपनेता राजनाथ ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के विषय पर चर्चा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि इससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। विपक्षी सदस्यों की मांग है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी सदन में बयान दें और चर्चा कराई जाए। हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मैं देख रहा

राजनाथ सिंह ने कहा, 'मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने खुद सर्वदलीय बैठक में यह बात कही थी। आज फिर मैं दोहराता हूं कि कुछ राजनीतिक दल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जिससे चर्चा नहीं हो। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना पर जितना गंभीर होना चाहिए, विपक्ष उतना गंभीर नहीं है।

मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने से पहले लोगों की हत्या की गयी : एफआईआर

एजेन्सी

इंफाल। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के संबंध में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन महिलाओं का अपहरण करने से पहले हथियारबंद पुरुषों का एक समूह कांगपोकपी जिले के गांव में घुसा और उसने घरों को लूटा तथा आगजनी की, लोगों की हत्या की तथा महिलाओं का यौन शोषण किया। एफआईआर में दावा किया गया है कि भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसने चार मई को कुछ लोगों को अपनी बहन से दुष्कर्म करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और दूसरे लोगों के सामने ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया। सैकुल थाने में दर्ज प्राथमिकी में दावा किया गया है, 'एके राइफल्स, एसएलआर, इनसास और .303 राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार लेकर करीब 900–1000 लोग सैकुल थाने से करीब 68 किलोमीटर दक्षिण में कांगपोकपी जिले में हमारे गांव में जबरन घुस आए।' प्राथमिकी में दावा किया गया है, 'हिंसक भीड़ ने हमारे घरों में तोड़फोड़ की और चल संपत्तियां लूटने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया।' इसमें कहा गया है कि वे नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनाज और मवेशियों को लूटकर ले गए। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ पांच लोगों को भी ले गयी थी जिन्हें पुलिसकर्मियों ने एक नजदीकी जंगल से बचाया। पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने तथा उनसे छेड़छाड़ करने के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 19 जुलाई को इस घटना का वीडियो सामने आया था। इस घटना के संबंध में एक महीने पहले 21 जून को सैकुल थाने में शिकायत दर्ज की गयी थी। जिन दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड करायी गयी, उनमें से एक का पति करगिल युद्ध में भाग ले चुका पूर्व सैनिक है जिन्होंने इस पर खेद जताया कि उन्होंने देश की रक्षा की लेकिन अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा पाए। वह असम रेजीमेंट में सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने एक स्थानीय समाचार चौनल से कहा, 'मैं करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ा और भारतीय शांति रक्षक बल के रूप में श्रीलंका में भी रहा। मैंने देश की रक्षा की लेकिन मैं निराश हूं कि मैं अपनी पत्नी तथा बाकी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका।' उन्होंने बताया कि चार मई की सुबह भीड़ ने इलाके में कई मकानों को फूंक दिया, दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र किया तथा उन्हें लोगों के सामने गांव की सड़कों पर घुमाया।

राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष

एजेन्सी

नयी दिल्ली। मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा को शुरुआती कामकाज के बाद फिर से स्थगित करना पड़ा। शुक्रवार को राज्यसभा में कौशल विकास, श्रम, वस्त्र, रक्षा, कृषि, पशुपालन आदि से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हालांकि शुरुआती कामकाज के बाद विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा सदन में उठाया जिसके बाद शुरू हुए शोर–शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत अनेक विपृक्षी दल राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए विपक्ष के विभिन्न सांसदों ने नोटिस भी दिया है। अधिकांश विपक्षी सांसदों का कहना है कि राज्यसभा में मणिपुर विषय पर चर्चा नियम 267 के तहत कराई जाए।

बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी के छलके आंसू

एजेन्सी

नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की कहानी बताते–बताते रो पड़ीं। अलीपुरद्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चटर्जी रो भी पड़ीं और भारी मन से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, जैसे मणिपुर है। उन्होंने कहा, ''हमारी बेटियां कहां जाएंगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चटर्जी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं की यह स्थिति तब है जब राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार की घटनाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और उनसे चुप्पी तोड़ने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई है। इसीलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुप हैं। बाकी प्रदेशों में जाकर ये लोग रोते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चुप हैं।

वहीं, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मणिपुर में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ द्वारा घुमाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में भी दो महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है। मजूमदार ने कहा कि दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी हुई दो घटनाओं का वीडियो उपलब्ध नहीं है। मजूमदार ने कहा, ''मणिपुर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के दक्षिण पांचला में भाजपा की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निवस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये मणिपुर से कम दुःखद घटना है? उन्होंने कहा, ''फर्क बस ये है कि इसका कोई वीडियो नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी (मुख्यमंत्री) की पुलिस और गुंडे किसी को भी वीडियो नहीं बनाने देते। भाजपा देश अध्यक्ष ने दावा किया कि एक ही दिन अलीपुर द्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) में दो महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया गया। उन्होंने आरोप लगाया, ''एक महिला को तो गधे पर नंगा करके गांव में घुमाया गया।श्श मजूमदार ने आगे कहा, ''कारण जो भी हो, इसमें राजनीतिक कारण नहीं है, अलग कारण है। अलग बात है। लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है वह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उससे सभी अवगत हैं।

अमरनाथ यात्रा के शेषनाग शिविर में झड़प, तीन लोग गिरफ्तार

एजेन्सी

अनंतनाग। अमरनाथ यात्रा के शेषनाग आधार शिविर में हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ तीर्थयात्रियों और टट्टूवालों को मामूली चोटें आई थीं। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) विजय कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक और निराधार वीडियो अपलोड किया है जिसमें दावा किया गया है कि तीर्थयात्रियों पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने कहा, मामले का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शेषनाग दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा के पहलगाम अक्ष पर स्थित है। एडीजीपी ने ट्विटर पर कहा, शेषनाग में 15 जुलाई को टट्टूवालों के बीच झड़प हो गई, जिसके परिणामस्वरूप टट्टूवालों और कुछ तीर्थयात्रियों को मामूली चोटें आईं। स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जनता को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। कुमार ने कहा, जम्मू–कश्मीर पुलिस तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और रहेगी।

महाराष्ट्रः रायगढ़ लैंडस्लाइड में 16 मौतें, 119 ग्रामीण अब भी लापता...बारिश के बीच रेस्क्यू जारी

एजेन्सी

रायगढ़। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में तलाश एवं बचाव अभियान शुक्रवार सुबह एक बार फिर शुरू कर दिया गया। एक दिन पहले यहां भारी भूस्खलन के कारण कई घर मलबे में दब गए थे, जिससे अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन बुधवार रात 11 बजे के आसपास मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर तटीय जिले की खालापुर तहसील में पहाड़ी ढलान पर स्थित एक आदिवासी गांव में हुआ। इस गांव के कुल 228 निवासियों में से करीब 16 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 93 के बारे में पता लगाया जा चुका है। वहीं, 119 ग्रामीण अब भी लापता हैं। अधिकारी के मुताबिक, लापता लोगों में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जो किसी शादी समारोह में शामिल होने या धान रोपाई के काम से बाहर गए थे। अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन के कारण गांव के लगभग 50 घरों में से 17 तबाह हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने रायगढ़ पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ दूसरे दिन भी बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारी ने कहा, ''एनडीआरएफ की कम से कम चार टीमों ने शुक्रवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। ठाणे आपदा मोचन बल, स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और रायगढ़ पुलिस की टीम भी बचाव कार्य में जुटी हुई है।

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे के मुताबिक, तलाशी अभियान सुबह छह बजकर 30 मिनट पर शुरू हुआ। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा, ''हमने तलाशी अभियान में कर्मियों की सहायता के लिए खोजी कुत्तों के एक दस्ते को भी शामिल किया है। बचाव और खोज टीमों ने गुरुवार को 16 शव बरामद कर लिए और 21 लोगों को बचा लिया। उन्होंने कहा, ''मृतकों में एक से चार साल की उम्र के चार बच्चे और 70 साल का एक बुजुर्ग शामिल है।

जयपुर में भूकंप के झटके

एजेन्सी

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार अलसुबह 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर के कई हिस्सों में सुबह लगभग चार बजे भूकंप के झटके महसूस होते ही घबराए लोग अपने–अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, जयपुर में भूकंप सुबह चार बजकर नौ मिनट पर करीब 10 किलोमीटर की गहराई में आया। एनसीएस के अनुसार, इसके बाद भारतीय समयानुसार सुबह चार बजकर 22 मिनट पर 3.1 तीव्रता और फिर सुबह चार बजकर 25 मिनट पर 3.4 तीव्रता का भूकंप का झटका आया। पुलिस नियंत्रण कक्ष ने कहा कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान या संपत्ति के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

मणिपुर पर हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

एजेन्सी

नयी दिल्ली। मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोक सभा की अगली बैठक, सोमवार 24 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी।मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के अंदर विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर सदन में चर्चा न हो। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच खड़े होकर कहा कि मणिपुर की घटना की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही यह कहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। सरकार मणिपुर पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्वयं यह सर्वदलीय बैठक में भी कहा था और आज इसे संसद में भी दोहराते हैं।

यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर बना लोगों के लिए संकट, श्मशान घाट तक पहुंचा पानी

एजेन्सी

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है जिसकी वजह से नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर अब संकट मंडराने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद का पानी श्मशान घाट के मुख्य द्वार तक पहुंच गया है, जिससे लोग काफी परेशान है। इटावा जिले से गुजरने वाली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। यमुना नदी के जल स्तर की बात की जाए तो इस वक्त नदी का जलस्तर 121.18 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। पानी अभी डेंजर लेवल से महज 74 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर नदी का जलस्तर और बड़ा तो नदी के किनारे बसे आस–पास के गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल बात की जाए तो अभी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद श्मशान घाट के मुख्य द्वार पर पानी आ गया है। जिससे लोगों के सामने अंतिम संस्कार करने का संकट आ सकता है। लोगों को अब भीरी डर लग रहा है कि नदी का जलस्तर और बड़ा तो हो नदी के किनारे बसे गांव में यमुना नदी का पानी पहुंच जाएगा। जिससे लोगों के सामने संकट आ सकता है। यमुना नदी के किनारे बने श्मशान घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने प्रशासन से मांग की है।

आरोप गंभीर, लेकिन हिरासत में लेने से कुछ हल नहीं होगा...बृजभूषण को जमानत देने पर बोला कोर्ट

एजेन्सी

नयी दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लयूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप "गंभीर" हैं लेकिन इस स्तर पर उन्हें हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के शुक्रवार को जारी आदेश में यह बात कही गई। कोर्ट ने गुरुवार को छह बार के भाजपा सांसद बृजभूषण को नियमित जमानत दे दी और डब्लयूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने गुरुवार को पारित अपने नौ पन्नों के आदेश में ये टिप्पणियां कीं। आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोप गंभीर हैं। मेरे विचार में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपों की गंभीरता जमानत आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन यह इसे तय करने का एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं है। जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखा जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होता है।" उन्होंने कहा, "मौजूदा मामले में, मेरी सुविचारित राय में, इस स्तर पर, आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" अदालत ने कहा कि सिंह और तोमर पर छेड़छाड़ध्यौन उत्पीड़न का आरोप है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल कैद की है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जांच में सहयोग किया। न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी स्तर पर, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से बोलते हुए, यह आशंका व्यक्त नहीं की है कि आरोपी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि जो बताया गया है वह यह है कि इस हद तक पर्याप्त शर्तें लगाई जानी चाहिए कि आरोपी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों को प्रभावित करने के लिए उनसे संपर्क न करें। न्यायाधीश ने कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध भी नहीं किया है, उनकी सहज दलील यह है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।" न्यायाधीश ने कहा कि पूछे जाने पर शिकायतकर्ताओं के वकील ने रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं दिया है जहां पीड़ितों को धमकी दी गई हो। वकील ने हालांकि यह आशंका व्यक्त की है कि आरोपी व्यक्ति पीड़ितों से संपर्क कर सकते हैं और भविष्य में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई विवरण नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि देश का कानून सभी के लिए बराबर है, इसे न तो पीड़ितों के पक्ष में खींचा जा सकता है।

सम्पादकीय

मणिपुर यौन हिंसा से सकते में देश

मणिपुर में ढाई महीने से जारी हिंसा के बीच बुधवार को वायरल हुए वीडियो में जिस तरह दो महिलाओं की निर्वस्त्र कर परेड कराये जाने का मामला सामने आया, उससे देश बेहद गुस्से व क्षोभ में डूब गया। राजनीतिक क्षेत्रों में भी उबाल आया और हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। घटनाक्रम से शीर्ष अदालत भी क्षुब्ध हुई। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताया कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो अदालत कार्रवाई करेगी। हालांकि, संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा कि घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है। इससे देश की बदनामी हुई है। साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा। हालांकि, विपक्ष लंबे समय से मणिपुर मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाता रहा है। सवाल यह भी उठाया जाता रहा है कि ढाई माह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसक संघर्ष रोकने के लिये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना मणिपुर के थोबल जिले में चार मई को घटी थी। सवाल उठता है कि परेड, अपहरण, गैंगरेप और हत्या की खबर क्या राज्य सरकार को नहीं थी? सोशल मीडिया में हकीकत सामने आने के बाद लीपापोती की कोशिश क्यों हो रही है? जिस एक साजिशकर्ता को अब गिरफ्तार करना दिखाया जा रहा है, उसे व उसके साथियों को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? बताते हैं कि अपराधियों ने पुलिस अभिरक्षा में गई महिलाओं को खींचकर यौन हिंसा की और परिवार सहित हत्या कर दी। घटना की भयावहता को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतरू संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में 28 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। निस्संदेह, इस घटनाक्रम के बाद डर, गुस्से व असुरक्षा में रह रहे दोनों समुदायों में हिंसा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सवाल मणिपुर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल, असली सवाल यह है कि मामले में 18 मई को प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? राज्य प्रशासन ने भी इस अमानवीय घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। यह एक अमानवीय घटना थी। जिसमें न केवल अपहरण, नग्न परेड, गैंगरेप, हत्याएं हुई बल्कि अपराधियों का दुस्साहस देखिये कि पीड़ितों की पहचान उजागर करने वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। भले ही इसके बाद महिला संगठनों द्वारा विरोध मार्च निकालने की घोषणा पर कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया हो, लेकिन घटना की गंभीर प्रतिक्रिया से इनकार नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, यौन हिंसा की घटना दिल दहला देने वाली है। वारदात बेहद शर्मनाक व निंदनीय भी है। किसी सभ्य समाज में जातीय कटुता के लिये महिलाओं को लक्षित करना एक घिनौनी हरकत ही कही जायेगी। ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को किसी धर्म, जाति व समाज में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। मणिपुर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ढाई माह की हिंसा में करीब डेढ़ सौ लोगों की मौत और साठ हजार लोगों के बेघर होने के बाद स्थिति को सामान्य बनाने के लिये उसने क्या प्रयास किये हैं? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम करेंगे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि थोड़े समय में जमीनी कार्रवाई न हुई तो कोर्ट एक्शन लेगा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो को आत्मा को झकझोर देने वाला बताते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन है। साथ ही यह भी कि महिलाओं को हिंसा के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शर्मनाक और अस्वीकार्य है। मानव जीवन का उल्लंघन है। साथ ही संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है।

मणिपुर में सरकार पूरी तरह से नाकाम

पिछले करीब ढाई महीनों से उत्तर पूर्व के एक राज्य मणिपुर में लगी हुई साम्प्रदायिक हिंसा की आग ने जहां एक ओर राज्य सरकार को पूरी तरह से नाकारा साबित कर दिया है वहीं दूसरी तरफ उस झुलसते प्रदेश से जो एक वीडियो सामने आया है वह सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार कर देने के लिये काफी है। वीडियो यह भी बतलाता है कि वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी है। इस वीडियो में 10–12 लोगों की भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रही है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है। एक की उम्र 21 वर्ष बताई गई है। कुछ और महिलाओं का भी उत्पीड़न हुआ परन्तु वे अपनी पहचान बचाये रखने के लिये वारदात वाले गांव से भागने में सफल रहीं। पीड़ित महिलाओं के साथ मारपीट भी की गयी। यह घटना कांगपोकपी जिले के बी फैलोम गांव की बतलाई जाती है जो 4 मई को हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पीड़ित महिलाएं कुकी जबकि आरोपी मैतेई बतलाये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कुकी वह आदिवासी समुदाय है जिसने ईसाई धर्म को अपना लिया है परन्तु वहां उनमें से कुछ को अनुसूचित जनजाति में तो कुछ को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया गया है। मैतेई समुदाय भी, जो कि हिन्दू है, खुद को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलनरत है। मई से ही दोनों समुदायों के बीच हो रही हिंसक भिड़ंतों में डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है और तकरीबन 500 लोग घायल हुए हैं। इन दंगों में बड़े पैमाने पर संपत्तियां भी जलाई या नष्ट की हुई हैं जो ज्यादातर कुकी लोगों की हैं। मणिपुर को इस हालत में पहुंचाने के लिये वहां की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह न तो वहां हिंसा को काबू में कर पा रहे हैं और न ही केन्द्र सरकार वहां को लेकर चिंतित दिखती है।

बीरेन सिंह एकाध बार जनता के सामने अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं लेकिन जिस नाटकीयता के साथ उन्होंने ऐसा किया उतनी ही ड्रामेबाजी दिखाते हुए उनके समर्थकों द्वारा वह त्यागपत्र फाड़ भी दिया जाता है। एक ओर जनता के सामने वे व्यथित होने तथा खुद को संवेदनशील जतलाने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि वह खुद मैतेई समुदाय को संरक्षण व अप्रत्यक्ष मदद दे रही है क्योंकि मैतेई प्रदेश में 52 फीसदी हैं जबकि कुकी अल्पसंख्यक (16 प्रतिशत) है। जाहिर है कि चुनाव जीतने के लिये बहुसंख्यकों का समर्थन चाहिये। इसे भाजपा के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयासों के रूप में भी देखा जाता है। अनेक विपक्षी नेताओं ने महिलाओं के साथ हुए इस अत्याचार पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। शायद विपक्ष का दबाव काम कर गया या श्री मोदी को अपनी छवि की फिक्र हुई, उन्होंने मानसून सत्र शुरु होने से पहले आखिरकार मणिपुर पर टिप्पणी कर ही दी। उन्होंने इस घटना को 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्म की बात बताई, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र भी कर गए। श्री मोदी मणिपुर के इस गंभीर संकट पर भी खुद को चुनावी राजनीति करने से रोक नहीं पाए। यह बेहद दुखद है कि यहां हिंसा फैलने से लेकर 75 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस विषय पर पूरी चुप्पी धारण किये रहे। 24 घंटे पूरी तरह से चुनावी मोड और बचे समय में विदेशी दौरों में रहने वाले श्री मोदी के पास कभी इतना समय नहीं हुआ कि वे मणिपुर जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सकें। सच तो यह है कि उन्होंने इस विषय पर न तो कोई बैठक की, न विपक्षी दलों के साथ विचार–विमर्श किया और न ही हिंसारत समुदायों से शांति की अपील की है। मणिपुर में जो स्थिति है उसके बारे में अब दुनिया भर में बात फैल चुकी है। हाल ही में जब मोदी विदेश यात्राओं पर गये थे तो कई सिविल सोसायटियों व यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने भारत में फैल रही साम्प्रदायिक वैमनस्यता व परस्पर हिंसा के जो उदाहरण दिये थे उनमें मणिपुर का भी जिक्र हुआ। भाजपा के कानों पर इसके बाद भी जूं तक नहीं रेंगी जो इस बात की आशंका को बल देती है कि क्या भाजपा इस हिंसा को मौन समर्थन दे रही है और इसका उपयोग हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण के लिये किया जा रहा है ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों समेत देश भर में हिन्दू बनाम ईसाई का वैसा ही माहौल बनाया जा सके जैसा कि वह हिन्दू बनाम मुसलमान करती आई है। वैसे भी देश भर के ईसाइयों पर भाजपा व उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा से वक्र दृष्टि रही है। अनेक राज्यों के जंगलों में शांतिपूर्ण जीवन गुजार रहे आदिवासी व उनमें भी खासकर धर्मांतरण कर चुके लोगों के साथ भाजपा के मनमुटाव व टकराव होते रहते हैं। विभिन्न सम्प्रदायों को आपस में लड़वाना सम्भवतरू भाजपा के राजनैतिक हित में तो हो सकता है लेकिन देश की अखंडता व एकता के लिये अत्यंत घातक है।

मणिपुर का दर्द कौन समझेगा

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले ढाई महीने से जो तांडव चल रहा है उसकी असलियत एक वीडियो ने पूरी दुनिया के सामने इस तरह बेनकाब की है कि इस राज्य के शासन में कानून और संविधान की सत्ता के स्थान पर पूर्ण अराजकता और अपराधियों की सत्ता कायम है और इस राज्य का मुख्यमन्त्री इस सबके बावजूद शान से अपनी कुर्सी पर विराजा हुआ है। ऐसे मुख्यमन्त्री को एक क्षण के लिए भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी निगेहबानी में कानूनी शासन और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विगत 4 मई को राज्य की दो आदिवासी महिलाओं को नग्न करके सार्वजनिक रूप से कुछ लोगों की भीड़ ने घुमाया और फिर बाद में उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उससे पूरी मानवता चीत्कार कर उठी है। मणिपुर में जिस तरह कुकी–जोमी जनजातियों की इन महिलाओं को राज्य की ही दूसरी जनजाति के लोगों ने जिस तरह अपनी पाशविकता और हैवानियत व हवस का शिकार बनाया उससे यही जाहिर होता है कि राज्य की एन. बीरेन सिंह सरकार पूरी तरह निकम्मी और नाकारा है जिसका कानून– व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण नहीं है। हद तो देखिये यह हुई कि मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में विगत 18 मई को ही कर दी गई मगर बीरेन सिंह तब तक आंख–कान पर पट्टी बांधे बैठे रहे जब तक कि इन महिलाओं की वीडियो प्रसारित नहीं हो गई। विगत 3 मई से मणिपुर में कोहराम मचा हुआ है और राज्य के निवासी एक–दूसरे के खून के प्यासे इस हद तक बने हुए हैं कि राज्य पुलिस में मैतेई और कुकी समुदाय के पुलिस के जवान भी आपस में एक–दूसरे पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी नफरत का जहर इन दोनों समुदायों के बीच बो दिया गया है जिसकी खेती रुक ही नहीं रही है। इस घटना से पूरा देश ही नहीं बल्कि संविधान का सर्वोच्च सिंहासन भी हिल उठा है और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकारों को चेतावनी दी है कि ऐसी खुल्लमखुल्ला संविधान के परखच्चे उड़ाने वाली घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती और यदि सरकार कोई यथोचित कार्रवाई नहीं करती है तो सर्वोच्च न्यायालय को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ की यह चेतावनी बताती है कि हमने अपने लोकतन्त्र की क्या हालत कर दी है लेकिन देखिये दूसरी तरफ देश की सबसे ऊंची लोकतान्त्रिक संस्था संसद के दोनों सदनों में क्या हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि मणिपुर के मामले पर अल्पकालिक चर्चा करा लो तो हम तैयार हैं मगर अगर विपक्ष इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के तहत पूरी चर्चा चाहता है तो उस पर सहमति नहीं है। यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं है क्योंकि सवाल यह है कि मणिपुर का मामला कोई सामान्य कानूनी अवहेलना का मामला नहीं है बल्कि संविधान के शासन को ही समाप्त करके उद्दढ़ निरंकुशता स्थापित करने का मामला है। ऐसे विषय पर संसद केवल आधे घंटे की चर्चा करके बहस की खानापूरी कर सकती है? संसद औपचारिकता पूरी करने की जगह नहीं है बल्कि लोगों की और देश की मूल समस्याओं से जूझने और उनका स्थायी हल ढूंढने की जगह है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि महिलाओं को नग्न करके घुमाये जाने जैसे अपराध को भी सामान्य कानून–व्यवस्था का मुद्दा मान रहे हैं। संसद की कार्यवाही से सरकार का कोई लेना–देना नहीं होता। यह कार्य संसद के दोनों सदनों के सभापतियों को अपनी स्वतन्त्र हैसियत से करना पड़ता है। ऐसे मामले में किस प्रकार संसद में केवल खानापूर्ति के लिए बहस की रस्म अदायगी हो सकती है और पूरे मामले को राजनैतिक फुटबाल बनाया जा सकता है। समाजवादी चिन्तक डा. राममनोहर लोहिया ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि जिस सवाल पर देश उबल रहा हो अगर उस पर संसद गूंगी बनी रहती है तो सड़कें आवारा हो जाती हैं। मणिपुर में आज जिस तरह कुकी–जोमी समुदाय के लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है वह इस बात का प्रतीक है कि भारत का यह सीमा प्रान्त अपना धैर्य खोता जा रहा है। संसद में पूर्ण बहस होने से समस्या का कोई हल निकलेगा क्योंकि मणिपुर की समस्या के पीछे राजनीति तो हो सकती है मगर मानवता के पीछे कोई राजनीति नहीं होती। मणिपुर केन्द्रीय सशस्त्र बल से लेकर सेना भी तैनात है। इसका मतलब यही निकलता है कि राज्य की बीरेन सिंह सरकार पूरी तरह लोगों का विश्वास खो चुकी है। लोकतन्त्र में सरकारें कभी भी लाठी–डंडे या पुलिस के बूते पर नहीं चलती है बल्कि 'इकबाल' के बूते पर चलती हैं और जिस सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है वह जनता का विश्वास खो देती है। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य भारत माता के माथे की शोभा है । इनका लहूलुहान स्वरूप पूरे भारत को भीतर से पीड़ा पहुंचाता है इसलिए संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर में संविधान का शासन स्थापित करने के प्रयास होने चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि संसद में सभी काम रोककर पूरी बहस कराई जाये जिससे मणिपुर की जनता को यह सन्देश जाये कि उनके इस दुख में पूरा भारत और इसका हर राजनैतिक दल शामिल है। दुख की घड़ियों में हमारे लोकतन्त्र की यह परंपरा रही है कि सभी राजनैतिक दल राजनीति छोड़ कर केवल लोगों की बात करते हैं। गांधी बाबा हमें यही पढ़ा कर गये हैं जिनके सिद्धान्तों को आज पूरी दिया अपना रही है।

चमोली हादसा: एक्ट ऑफ मैन

आदित्य नारायण

उत्तराखंड, हिमाचल और अन्य पहाड़ी राज्यों से रोजाना प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मौतों की खबरें आ रही हैं। कभी पहाड़ खिसकने से मौतें हो रही हैं तो कभी भारी बारिश लोगों को बहा ले जाती है। प्राकृतिक आपदाओं पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें एक्ट ऑफ गॉड यानि दैवीय आपदा मानकर इतिश्री कर ली जाती है। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान कर सरकारें खामोश हो जाती हैं लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे परियोजना के तहत जल–मल शोधन संयंत्र में करंट फैलने से हुई 16 मौतों को एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जा सकता। यह हादसा एक्ट ऑफ मैन है। हृदय विदारक घटना महज एक हादसा नहीं है, बल्कि यह घोर लापरवाही का परिणाम है। आमतौर पर बारिश के दिनों में बिजली यंत्रों के सही रखरखाव न होने के कारण करंट फैलने की घटनाएं होती रही हैं। यह घटना भी बिजली संयंत्रों के उचित रखरखाव और परियोजना पर सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रबंध न होने के कारण घटित हुई परिलक्षित होती है। 16 लोगों की मौत से पहले मंगलवार की रात को ही वहां घबिघ्जली की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार की सुबह जब मृतक का पंचनामा चल रहा था तब फिर से वहां रेलिंग में करंट दौड़ गया। अब सवाल यह उठता है कि जब करंट से एक की मौत हो चुकी थी तो क्यों नहीं प्लांट की घबिजली सप्लाई बंद की गई। प्रोजैक्ट को देख रहे प्रबंधकों ने क्यों नहीं करंट फैलने के कारणों और खामी को दूर करने का काम किया। यह सीधे–सीधे मानव जनित हादसा है, जिसके लिए परियोजना का तंत्र दोषी है। इस ट्रीटमैंट प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी एक कम्पनी के पास है जिसके साथ 15 सालों का अनुबंध किया गया है। सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट पूरा टीन से बना है। ऐसे में करंट सभी जगह फैल गया। आमतौर पर बिजली सप्लाई बाधित होने की मामूली समस्या को दूर करने से पहले घबिजली का सम्पर्क काटा जाता है। पहले मरम्मत की जाती है फिर घ्बिजली की सप्लाई की जाती है। यद्यपि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात की है लेकिन जिन लोगों की घ्जिन्दगी चली गई उसकी भरपाई न तो सरकार कर पाएगी और न ही समाज। सरकारी मुआवजा भी जीवन भर उनके आंसुओं की कीमत अदा नहीं कर सकता। ओडिशा के बालासोर में हुए भयंकर ट्रेन हादसे में 293 लोगों की मौत के बाद जब जांच सीबीआई ने शुरू की तो एक के बाद एक खुलासा हुआ कि ट्रेन त्रासदी लापरवाही और मानवीय भूल के कारण हुई थी। अब एक–एक करके अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं और कुछ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हादसे तब होते हैं जब तकनीकी पहलुओं को नजरंदाज कर दिया जाता है। गुजरात का मोरबी पुल हादसा मानवीय लालच और लापरवाही का नतीजा था। जांच से ही पता चला था कि पुल के रेनोवेशन के लिए महज 12 लाख रुपए खर्च किए गए थे जबकि रेनोवेशन करने वाली कम्पनी को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गएध्थे। मोरबी पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। आज निर्माणाधीन पुल बह जाते हैं। कुछ दिन शोर मचता है फिरर हम नए हादसे का इंतजार करते हैं। परियोजनाएं तभी कामयाब होती हैं जब टैक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। प्रबंधन जब लापरवाही करता है या देखरेख करने वाली कम्पनियां लालच के कारण नियमों की अनदेखी करती हैं तो ऐसे हादसे होते ही हैं। विडम्बना यह है कि हम हादसों से सबक नहीं लेते और हम यह ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं समझते कि अगर खामियों को दूर करने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए तो इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी को दोषी ठहराकर उसे बर्खास्त कर दिया जाता है लेकिन ऐसे हादसों के लिए समूचे तंत्र को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। चमोली का हादसा समूचे तंत्र की लापरवाही का ही परिणाम है। क्यों नहीं इस हादसे के लिए यूपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया जाता। अब तो नमामि गंगे प्रोजैक्ट के तहत घटिया निर्माण और घटिया यंत्र लगाने में भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठने लगी है। चमोली हादसे के लिए जिम्मेदारों पर सामूहिक हत्या का मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कठघरे में खड़ा करें और ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करें।

समान संहिता पर अनुचित आपत्तियां

कुरान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को व्यवस्थित करने का एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग केवल तभी संभव है, जब ईश्वर का दूत यानी पैगंबर स्वयं धरती पर हो (कुरान 42ध्13, 09ध्33)। यदि ईश्वर का दूत धरती पर नहीं है तो मुस्लिमों को इस्लामी राज्य के अधीन होना अनिवार्य नहीं है। कुरान के साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम होने के लिए किसी व्यक्ति को अल्लाह में विश्वास, पांच बार की नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, साल में एक बार जकात देना और यदि संभव हो तो हज करना आवश्यक है। जब कोई मुस्लिम किसी इस्लामी राज्य में न हो तो फिर वहां की नागरिक एवं दंड संहिता का इस्लामी होना आवश्यक नहीं होता।

ताहिर अनवर

जबसे समान नागरिक संहिता लागू करने की बात छिड़ी है, तबसे आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और दूसरे कई मुस्लिम संगठनों के साथ अनेक दल इस संहिता का विरोध करने में जुटे हैं। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को इस्लाम के शरिया कानून के विरुद्ध गैर–इस्लामी बताया है। उसके अनुसार किसी मुसलमान की ओर से इस संहिता को नहीं अपनाया जा सकता। चूंकि मैं स्वयं इस्लाम का अनुयायी एवं शोधार्थी हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की इस अनुचित आपत्ति की असलियत सभी नागरिकों और विशेष रूप से मुस्लिम भाई–बहनों के सामने रखूं, ताकि वे इस्लाम की सही शिक्षाओं को समझते हुए मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसी स्वयंभू संस्थाओं के मनचाहे इस्लाम से पीछा छुड़ाएं और कुरान तथा पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में दिए गए निर्देशों के अनुरूप भारतीय संविधान का पालन करें। समान नागरिक संहिता का राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समान होना अनिवार्य है। भारत में सभी नागरिकों के लिए समान संहिता बनाने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 44 में है। जब इस्लाम का उदय हुआ, तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्राथमिक रूप से लोगों में एक ईश्वर के प्रति आस्था और शिष्टाचार लाने के उपरांत वहां की परिस्थितियों के अनुरूप एक इस्लामी राज्य की स्थापना की। इसका उद्देश्य सभी मुस्लिमों और दूसरे नागरिकों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखना था। कुरान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को व्यवस्थित करने का एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग केवल तभी संभव है, जब ईश्वर का दूत यानी पैगंबर स्वयं धरती पर हो (कुरान 42ध्13, 09ध्33)। यदि ईश्वर का दूत धरती पर नहीं है तो मुस्लिमों को इस्लामी राज्य के अधीन होना अनिवार्य नहीं है। कुरान के साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम होने के लिए किसी व्यक्ति को अल्लाह में विश्वास, पांच बार की नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, साल में एक बार जकात देना और यदि संभव हो तो हज करना आवश्यक है। जब कोई मुस्लिम किसी इस्लामी राज्य में न हो तो फिर वहां की नागरिक एवं दंड संहिता का इस्लामी होना आवश्यक नहीं होता। कुरान में स्पष्टता से कहा गया है कि ईश्वर में आस्था रखना और अच्छे कर्म करना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। यही बात हदीसों में भी बार–बार साफ तौर पर कही गई है। इसी सबकी पुष्टि भारतीय मुसलमान निरंतर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपराधिक मामलों में वे भारतीय दंड संहिता को बिना किसी आपत्ति के अपनाए हुए हैं। अतः यह कहना कि ईश्वर की किताब में बताए गए कानूनों एवं दिशानिर्देशों के पालन के बिना कोई व्यक्ति इस्लाम में नहीं रह सकता, एक अंतर्विरोध भरी गलत बात है। इसे भी समझ लिया जाना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल ला इस्लाम की किताबों पर उलेमाओं की अपनी–अपनी समझ का नतीजा हैं, न कि कुरान और हदीस में बताई गई बातों का एकमत स्वरूप। अगर शरिया कानून कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुरूप होता तो फिर मुस्लिम समाज में उसे लेकर अलग–अलग व्याख्याएं नहीं होतीं। हाल में किए गए कुछ सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है कि देश में तमाम मुस्लिम महिलाएं इस्लामी किताबों की अलग–अलग व्याख्याओं के माध्यम से बनाए गए मुस्लिम पर्सनल ला की जगह समान नागरिक संहिता को अपनाना चाहती हैं। एक मीडिया संस्थान ने देश के 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आठ हजार से भी अधिक मुस्लिम महिलाओं से समान संहिता पर राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इनमें अधिकतर महिलाओं ने बहुविवाह पर आपत्ति जताई, संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की और गोद लेने के मामले में छूट की पैरवी की। यह सर्वेक्षण इसका प्रमाण है कि भारत में अधिकतर मुस्लिम महिलाएं पर्सनल ला कानून से पीड़ित होकर समान नागरिक संहिता चाह रही हैं। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का एक तर्क यह भी है कि चूंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, अतः यहां समान नागरिक संहिता लागू करना अनुचित होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान इस संहिता को संविधान विरोधी कह रहे हैं। ये दोनों ही कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का खुला विरोध हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता की कल्पना तो संविधान में ही प्रस्तावित है। हमारे संविधान निर्माता इससे भली भांति अवगत थे कि भारत विविधताओं से भरा देश है। वास्तविकता यह है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत की विविधता को समाप्त करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को बराबरी का अहसास कराना है। समान नागरिक संहिता को लेकर अनुच्छेद 44 का खुला विरोध यही स्पष्ट करता है कि कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस संहिता पर आपत्ति जता रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे इस्लाम से जुड़ी किताबों एवं भारतीय संविधान का स्वयं अध्ययन करें और यह समझें कि इस्लाम न तो किसी दूसरे पंथ के प्रति बैर का संदेश देता है और न ही संविधान एवं देश के प्रति असम्मान प्रकट करने का। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस्लाम या किसी अन्य मत के विरुद्ध कोई बात नहीं है। भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य सभी मतों के लोग संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। ऐसे में दंड संहिता की तरह समान नागरिक संहिता से ही संविधान की मनोकामना पूरी होगी और राष्ट्र की एकता को बल मिलेगा। कुरान की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य ईश्वर की इच्छानुसार लोगों को व्यवस्थित करने का एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग केवल तभी संभव है, जब ईश्वर का दूत यानी पैगंबर स्वयं धरती पर हो (कुरान 42ध्13, 09ध्33)। यदि ईश्वर का दूत धरती पर नहीं है तो मुस्लिमों को इस्लामी राज्य के अधीन होना अनिवार्य नहीं है। कुरान के साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, जिन्हें हम हदीस कहते हैं, को पढ़ने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम होने के लिए किसी व्यक्ति को अल्लाह में विश्वास, पांच बार की नमाज अदा करना, रमजान के महीने में रोजा रखना, साल में एक बार जकात देना और यदि संभव हो तो हज करना आवश्यक है। जब कोई मुस्लिम किसी इस्लामी राज्य में न हो तो फिर वहां की नागरिक एवं दंड संहिता का इस्लामी होना आवश्यक नहीं होता। कुरान में स्पष्टता से कहा गया है कि ईश्वर में आस्था रखना और अच्छे कर्म करना किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है।

समाधान दिवस पर जो भी पीड़ित आएं, उन्हें न्याय दिलाना सुनिश्चित करें :डीएम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व विकास श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा की उपस्थिति में थाना बक्सा में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाधान दिवस में गंभीरता से प्रकरणों की सुनवाई की जाए और जो भी मामले आएं, उनमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि फरियादियों को त्वरित न्याय मिल सके। मौके पर निस्तारित न हो पाने वाले मामलों के निस्तारण के लिए संयुक्त टीम गठित करें और निर्धारित समय में जांच कराकर उसका समाधान कराएं। अधिकारियों ने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य है कि राजस्व और पुलिस विभाग के लोग एक साथ मौजूद रहें। जो भी पीड़ित आएं, उन्हें न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 04 का मौके पर निस्तारण किया गया और 02 ठीमें भेजी गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर सुनील कुमार, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी शिवानी सिंह, कुणाल गौरव उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड जौनपुर ने कराया वृक्षारोपण : किसान चौपाल

लगाकर सुनी ग्रामीणों की सिंचाई समस्याएं : मौके पर कराया शिकायतों का निस्तारण

जौनपुर (दै0 देश की उपासना संवाददाता) विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर अंतर्गत सिंचाई मंत्री के आदेशानुसार कल दिनांक–21.07.2023 को नलकूप खण्ड जौनपुर के अधिशासी अभियंता अरूण सिंह राणा एवं पंचम उपखण्ड के सहायक अभियंता सुधीर कुमार सिंह की मौजूदगी में किसान चौपाल का आयोजन 41 एम0एस0जी0 ग्राम–इटहरा, 154 व 33 एम0एस0जी0 ग्राम–रखौली, 29 एम0एस0जी0 ग्राम–हसनपुर, विकास खण्ड–मुंगराबादशाहपुर में किया गया, किसानों की समस्याओं पर सिंचाई से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई तथा मौके पर अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया। मौके पर सभी नलकूप चालू हालत में पाये गये। किसान चौपाल में अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंता दीपक सिंह, जिलेदार राकेश दूबे, सींचपर्यवेक्षके तीर्थराज सिंह, सेक्शन मिस्त्री बृजेश कुमार, सींचपर्यवेक्षक धनंन्जय सिंह, इन्द्रजीत, दिनेश कुमार, महेन्द्र श्रीवास्तव व नलकूप चालक भात्रुघन कुमार, विपिन कुमार, अजय सिंह, मनीश पाल, रविकान्त, सिद्धार्थ भाुक्ला, अजीत कुमार ने मौके पर उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया। किसान चौपाल में स्थानीय ग्रामीण किसानों में राजेन्द्र कुमार मौर्य, विजय कुमार उर्फ लल्लु, उमाकान्त मौर्य इत्यादि किसानगण मौजूद रहे, किसान चौपाल में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य इन्द्रबहादुर कनौजिया तथा अन्य कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियंता द्वारा जिला मुख्यालय पर शासन एवं विभागीय उच्चाधिकारियों की मंशा अनुसार आज वृक्षारोपण किया एवं कराया गया जिसमें उनके साथ–साथ खण्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा भी वृक्षारोपण करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वृक्षारोपण में सहायक अभियंता प्रथम जयप्रकाश, अवर अभियंता मुख्यालय निर्भयराम, अवर अभियंता भोरसिंह विश्वकर्मा, सुनील कुमार राय एवं खण्ड के प्रशासनिक अधिकारी, दशरथ कुमार सिंह प्रधान सहायक, मयंक यादव स्टेनों, बृजेश श्रीवास्तव, अभिशेक श्रीवास्तव, संदीप कुमार चौबे, मौ0 मेराजुद्दीन , साहबलाल, मनीश श्रीवास्तव, हौंसिला प्रसाद कैशियर, राहुल, कन्हैयालाल प्रारूपकार आदि कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया।

प्रकृति को बचाने के एकमात्र विकल्प वृक्षारोपण'नारे को किया चरितार्थ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लायंस क्लब क्षितिज के सदस्यों द्वारा 'प्रकृति को बचाने के एकमात्र विकल्प वृक्षारोपण ' नारे को किया चरितार्थ करते हुए वृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रम उर्दू बाजार स्थित महादेव शक्ति धाम ,रामलीला मैदान चौराहा में अशोक , आम, पीपल, नीम, मौलश्री, बरगद आदि के छायादार सहित आर्नामेंटल प्लांट्स के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही पुराने वृक्षों की देखभाल की गई जिसमे सभी लायन साथियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

जोन चेयरपर्सन लायन विष्णू सहाय ने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और वायुमंडल में फैले प्रदूषण को कम करें जिससे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिल सके। लायंस क्लब क्षितिज के अध्यक्ष लायन धर्मेन्द्र सेठ ने सभी का स्वागत करते हुये कहा कि हमें संकल्प लेना है कि हम धरती की हरियाली को बढ़ाएंगे। संस्थपाक अध्यक्ष लायन शशांक सिंह रानू ने अपील किया कि हमें पेड़ लगाकर धरती को हरा–भरा करना है। इस अवसर पर जयकृष्णा साहू, विनय बरौतिया, अतुल सिंह, देव आनन्द, संजय बैंकर, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव , डा. सतीश सिंह, सर्वेश गुप्ता, हाफिज शाह, रत्नेश जी आदि उपस्थित रहे। अन्त में संयोजक देवेश ने समस्त आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

वृक्षारोपड़ का आनंद दिखा, गोमती रिवर फ्रंट पर

गोमती रिवर फ्रंट उद्यान में डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के वास्तुकला एवं योजना संकाय द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम।

लखनऊ। वृक्ष हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिनके बिना जीवन का चक्र पूरा नहीं होता। ये पर्यावरण के आवश्यक अंग है इनकी अधिकाधिक उपस्थिति वर्षा का कारण बनती है साथ ही भूमि क्षरण को भी रोकती है। पिछले वर्षों में आधुनिक विकास के कारण वृक्षों की घटती संख्या चिंताजनक थी। वातावरण में बढ़ते प्रदुषण एवं कार्बनडाई ऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वॉर्मिंग जैसे विपदा में सहायक बन रही थी। वृक्ष ही एक सर्वोत्तम उपाय है जो वातावरण में उपस्थित कार्बन को कम करने में मददगार है। कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि वृक्षों कि घटती संख्या के प्रति जनमानस में एक चेतना फैल रही है। लोगबाग उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण करने को उत्सुक है और कर भी रहे हैं। अपने आस पास मोहल्ले नगर में वृक्षारोपण को उत्सव कि तरह आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लखनऊ

स्थित गोमती रिवर फ्रंट उद्यान में डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के वास्तुकला एवं योजना संकाय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ ए पी जे अब्दुल कलम प्राविधिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जे पी पांडेय,डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी (वी सी एल डी ए) वास्तुकला एवं योजना संकाय की प्राचार्य एवं अधिष्ठाता डॉ वंदना सहगल एवं विभागाध्यक्ष डॉ रितु गुलाटी सहित संकाय के सभी प्राध्यापक डॉ सुब्रजीत बनर्जी,डॉ इन्द्राणी चक्रवर्ती, डॉ मीता टंडन,डॉ आंजनेय शर्मा, राकेश पैजवार, गिरीश पांडेय, ताबिश अहमद, प्रभात कुमार राव, लक्ष्मी कांत मिश्रा, शिव विनय राय, अखिलेश पांडेय, रचना पांडेय, भूपेंद्र कुमार अस्थाना, प्रियंका रस्तोगी,दिव्या पांडेय, महिमा ठुस्सू, दिव्यांशी श्रीवास्तव, प्रसून मिश्रा, शिशिर ,सावन वर्मा, राजकिशोर सहित संकाय के लगभग 40 छात्र, छात्राओं की उपस्थिति रही। उपस्थित सभी लोगों ने एक एक पौधे लगा कर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में संकाय के साथ सहयोग में लखनऊ विकास प्राधिकरण और जंगल विभाग उत्तर प्रदेश रहे । जंगल विभाग ने 300 पौधे उपलब्ध कराये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्थान उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम के को ओर्डिनेटर डॉ आंजनेय शर्मा और प्रसून मिश्रा रहे।

— भूपेंद्र कुमार अस्थाना —
9452128267 , 7011181273

डीएम व पुलिस अधीक्षक ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जनपद के तमाम अधिकारियों ने अपने–अपने कार्यालय व आसपास क्षेत्रों में वृहद रूप से पौधारोपण किया तो वही इस कार्य में सबसे पहले जनपद के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा खंड विकास अधिकारी बक्सा परिसर में पीपल एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के द्वारा आम का पौधा लगा कर इसका शुभारंभ किया गया।इसी क्रम में विकासखंड बक्सा के ही भटपुरवा गाँव मे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर द्वारा आम का वृक्ष लगाया गया।

डायट परिसर में किया गया वृक्षारोपण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद जौनपुर में ष्पेड़ लगाओ पेड़ बचाओष् वृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत आज उप शिक्षा निदेशकध्प्राचार्य डॉ.विनोद कुमार शर्मा द्वारा अपनी समस्त टीम के साथ वृहद वृक्षारोपण किया गया वृक्षारोपण में वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. आर. एन. यादव, समस्त प्रवक्ता, समस्त प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा वृक्षारोपण किया और वृक्षों के रख– रखाव तथा संरक्षित रखने की प्रतिज्ञा भी ली गई स कार्यक्रम का संचालन श्री अमित कुमार, श्री अखिलेश कुमार मौर्य प्रवक्ता द्वारा किया गया।

वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विभाग की नवागत जिला उद्यान अधिकारी डा0 सीमा सिंह राणा द्वारा कृषि भवन कैम्पस में शिव मंदिर के प्रागंण में पीपल, बरगद, बाटलब्रश, आवंला बेल आदि पौधो का रोपण विभागीय कर्मचारियो की उपस्थिति में किया गया।

वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा 22 जुलाई 228833 पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग के ब्लाक प्रभारी द्वारा पौध रोपण का कार्य करके वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया गया। पौध रोपण कार्यक्रम में ग्राम बस्तीबन्द विकासखण्ड खुटहन में विधायक रमेश सिंह के पैतृक गांव में विभाग द्वारा आम का पौध रोपण कराया गया साथ ही साथ विकासखण्ड धर्मापुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरगांव व इग्लिश मीडियम प्राइमरी पाठशाला उत्तरगांव मुसहर बस्ती में स्कूलीय बच्चो को निःशुल्क पौध वितरण के साथ ही पौध रोपण कर पौधे को सुरक्षित रखने हेतु संकल्प दिलाया गया तथा जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बच्चो से उनके जन्मदिवस एंव माता–पिता के शादी की सालगिरह पर कम से कम 1–1 पौध लगाने की अपील की गयी। पौध वितरण के समय मौके पर उद्यान निरीक्षक रविन्द्र सिंह, पीयूष सिंह, कनिष्ठ सहायक, विवेक रंजन एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहें।

हिन्दी भक्तिएलबम त्रिलोचन धाम हो की शूटिंग संपन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जलालपु क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव निवासी रियल हीरो की मिशाल पैदा करने वाले क्षेत्रिय भोजपुरी फिल्म अभिनेता चन्दन सेठ की रागलोक म्युजिक कंपनी के बैनर तले बन रहे हिन्दी भक्ति एलबम त्रिलोचन धाम हो की शूटिंग प्राचीन व ऐतिहाशिक त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर व तालाब के इर्द–गिर्द स्थलों पर फिल्माया गया।जिसका उद्घाटन जलालपुर एसओ व त्रिलोचन महादेव मंदिर कमेटी के प्रबंधक मुरलीधर गिरि ने किया।मंदिर के महंत अशोक गिरि व नितेश दूबे ने विधिवत पूजा–पाठ कर शूटिंग प्रारम्भ करवाया।फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए अभिनेता चन्दन ने बताया कि इस एलबम में पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध गायक सौरभ पंडित ने अपनी सुमधुर आवाज से सवारा है इस गाने में मैं मुख्य किरदार में हूं।एलबम के डायरेक्टरध्कैमरामैन जिग्नेश मौर्य भ्रमर,गीत सौरभ पंडित,मेकअप मैन राजा गिरि,डीओपी रॉकी यादव,अर्पित यादव,पीआरओ सुनिल प्रजापति,कोरियोग्राफर हजारी लाल यादव ने किया है।चन्दन ने बताया यह गीत 2023 का अब तक का सबसे हिट त्रिलोचन महादेव धाम गीत साबित होगा।जो लोगों को काफी पसन्द आयेगा।उन्होने बताया उनका आने वाला हिन्दी विडियो एलबम बेवफा की याद,रात कटे तारे गिन गिन समेत दर्जनों हिन्दी व भोजपुरी एलबम की गाने की रिकार्डिंग पुरी हो गयी है जिसकी शूटिंग अतिशीघ्र जौनपुर व वाराणसी जिले के आस पास रमणीय स्थलों पर की जायेगी।

सीतापुर में घाघरा नदी में फ्लड यूनिट ने किया मॉकड्रिल

नदी में डूब रहे तीन युवकों को टीम ने बचाया, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को किया जागरूक

सीतापुर (संवाददाता)। सीतापुर में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा मॉकड्रिल रिहर्सल कार्यक्रम चहलारी घाट स्थित पुल के नीचे घाघरा नदी में किया गया। इस दौरान बाढ़ के समय में गांव के ही डूब रहे 3 लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने नदी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला और स्वास्थ्य कैंप में प्राथमिक उपचार डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया। इन रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार के दौरान दो की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। चहलारी घाट पर जिला प्रशासन के इस मॉकड्रिल से ग्रामीण काफी हतोत्साहित दिखे। रेउसा के चहलारी घाट पुल के नीचे एनडीआरएफ और पीएसपी पुलिस बल तहसील, प्रशासन सिंचाई विभाग पुलिस टीम व स्वास्थ्य टीम द्वारा मार्क ड्रिल रिहर्सल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गौलोक कोड़र, चहलारी, नागिनापुरवा, श्यामनगर और सुंदर नगर गांव मे बाढ़ के दौरान घाघरा नदी का पानी ग्रामीणों के घरों मे भर जाने के बाद एक नाव पर गांव के करीब आधा दर्जन ग्रामीण पलायन कर सुरक्षित स्थान की तरफ से जा रहे थे। इस दौरान घाघरा नदी में नाव पलट गई,जिसमें तीन लोग डूब रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों द्वारा नदी में छलांग लगाकर डूब रहे तीनों ग्रामीणों को नदी के बाहर सुरक्षित निकाला गया। इस मॉकड्रिल के बाद स्वास्थ्य शिविर कैंप में उपचार हेतु भेजा गया। इस दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान जल विभाग द्वारा गांव के ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि बाढ़ के समय सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट नाव पर क्षमता से अधिक लोग ना बैठे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ के समय अनेकों बीमारियां फैलती हैं। जिससे बचाव के लिए स्वास्थ्य टीम हर समय आपके बाढ़ चौकी पर मौजूद रहेगी। तहसील प्रशासन और पुलिस से विभाग द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि रात्रि में नदी व नाला के किनारे ना जाएं बच्चों पर ज्यादा ध्यान रखें जंगली जीव जंतु बाढ़ के समय आ जाते हैं रात्रि में उजाला के लिए लालटेन सौर ऊर्जा लाइट मोमबत्ती आदि का प्रयोग करें। इन रेस्क्यू और प्राथमिक उपचार के दौरान दो की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। चहलारी घाट पर जिला प्रशासन के इस मॉकड्रिल से ग्रामीण काफी हतोत्साहित दिखे। रेउसा के चहलारी घाट पुल के नीचे एनडीआरएफ और पीएसपी पुलिस बल तहसील, प्रशासन सिंचाई विभाग पुलिस टीम व स्वास्थ्य टीम द्वारा मार्क ड्रिल रिहर्सल प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

सीटी स्कैन की फीस बताकर युवक ने ले लिए 600 रुपये

हरदोई (संवाददाता)। लाख कोशिशों के बाद भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ हो रही अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है। इसी तरह का एक मामला गुरुवार को प्रकाश में आया है। सीटी स्कैन की जांच कराने आए युवक को एक व्यक्ति ने सरकारी फीस की बात कहकर 600 रुपये ले लिए। ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से शिकायत की है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के खंनिगवा कला निवासी सुदामा प्रसाद के कमर से में काफी दिनों से दर्द है। जिसके कारण एक पैर में काफी दिक्कत बनी हुई है। इसके कारण चलने में असुविधा हो रही है। सुदामा ने बताया कि बुधवार को सीटी स्कैन कराने के लिए स्वसाशी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में स्थित सीटी स्कैन कक्ष के पास गया था।

वृक्ष जलवायु के साथ पर्यावरण व जन्तु संतुलन मे निभाते हैं मुख्य भूमिका - ऋतु सिंह

आरटीओ ने एआरटीओ प्रशासन व आरआई के साथ आरटीओ कार्यालय व डीटीटीआई में किया पौधरोपण

अयोध्या। शनिवार को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत शासन की मंशा अनुरूप मुख्य अतिथि व आरटीओ ऋतु सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग द्वारा बारह सौ पौधे व पेड़ ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अयोध्या के साथ साथ आरटीओ कार्यालय में रोपित किए गए।इस मौके पर उन्होंने पीपल, सागवान, आम जामुन,अमरूद,आंवला,नीम,अर्जुन आदि के पौधे वृक्षारोपण के दौरान रोपित किए गए।इस अवसर पर आरटीओ ऋतु सिंह ने कहा कि हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कार्य करना चाहिए। क्योंकि वृक्ष पृथ्वी पर जलवायु संतुलन पर्यावरण संतुलन एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मृदा संरक्षण कर बाढ़ व सूखे की स्थिति को भी उत्पन्न नहीं होने देते ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिगत यह आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। वही हम सभी को खास अवसरों जैसे जन्मदिन नया साल या कोई पर्व त्योहार इत्यादि पर पेड़ पौधे उपहार में दें वह उन्हें संरक्षित भी करें। इस अवसर पर एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि अगर हम किसी कारण एक वृक्ष काटे तो उसके बदले कई वृक्ष लगाए।उन्होंने सभी डीलर्स को भी वृक्षारोपण हेतु निर्देश दिए गए थे।आर आई प्रेम सिंह ने बताया कि आज डीटीटीआई में 800 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया गया वही 400 पौधे आरटीओ कार्यालय में लगाये गए।इस मौके पर वहां पर मुख्य अतिथि के रुप में आरटीओ ऋतु सिंह के साथ साथ आरटीओ प्रशासन आर पी सिंह व आर आई प्रेम सिंह ने मौजूद कर्मचारियों ने उपस्थित अधिकारियों ने वृक्षारोपण के इस अभियान को निरंतर जारी रखने की शपथ भी ली।

फिल्म बैन की मांग वाली याचिका खारिज

संवाददाता/लखनऊ। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दाखिल जनहित याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट द्वारा निर्माताओं बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विवादास्पद फिल्म "आदिपुरुष" को लेकर कहा कि महाकाव्य रामायण से प्रेरित "आदिपुरुष" की उसके संवादों और बोलचाल की भाषा के उपयोग के लिए आलोचना हो रही है।

खनन से हुआ गड्ढा, छिन गईं चार जिंदगियां

बच्चों के शव देख कांप गए मां-बाप, DM बोले- गहराई की होगी जांच पड़ताल

हरदोई (संवाददाता)। हरदोई जिले में पचदेवरा थाना क्षेत्र के मैकपुर गांव में खनन से हुए गड्ढे में डूबकर चार मासूमों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। मृतकों और इनके पड़ोसियों के घरों में चूल्हे नहीं जले। उधर, दूसरी ओर डीएम ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खनन के लिए खेत मालिक से अनुमति लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही खनन किया था। जांच इस बात की होनी है कि कहीं तय मानक से अधिक का खनन तो नहीं किया गया है। इसके लिए शनिवार को शाहाबाद तहसील की एक टीम मौके का निरीक्षण कर पड़ताल करेगी। मैकपुर गांव में साबिर के पुत्र अजमत और सद्दाम व शौकीन की पुत्री खुशनुमा और पुत्र मुस्तकीम खेलते समय खेत के गड्ढे में भरे पानी में नहाने गए थे। इसी दौरान डूबने से चारों की मौत हो गई। राजस्व विभाग से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेस–वे का निर्माण करने वाली कंपनी को निर्माण कार्यों में मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसानों से बात कर उधार क्षेत्र अनुमोदन और एनओसी ली जाती है। कुरारी में गाटा संख्या 40,32 और 149 (मी) में खनन की अनुमति ली गई थी। खनन का कार्य 16 जून 2023 से 14 अगस्त 2023 के बीच किए जाने की अनुमति दी गई थी। जिन लोगों के खेतों में अनुमति दी थी उनमें शेर बहादुर, ओमदेवी, हरिहर सिंह, मुखराम और शब्बीर अहमद हैं। जारी अनुमति के मुताबिक संबंधित कार्यदायी संस्था 1.8 मीटर (लगभग छह फीट) गहराई तक ही खनन किया जा सकता है।

मेडिकल कैंप में लोगों को मुफ्त दवाएं दी गयी

संवाददाता

लखनऊ। भारत सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आरईसी लिमिटेड द्वारा मदद सहयोग गाइडेंस फाउंडेशन (द एमएसजी फाउंडेशन) के सहयोग से सादतगंज, लखनऊ में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर द्वारा लगभग 180–190 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। इस चिकित्सा शिविर के हिस्से के रूप में, विभिन्न बीमारियों से जुड़े जोखिम कारकों को कम करने के लिए पूरे शरीर की व्यापक जांच की गई। शिविर के दौरान दी जाने वाली सेवाओं में रक्त शर्करा के स्तर की जांच, मुफ्त चिकित्सा परामर्श और बुखार, फ्लू, खांसी, दृष्टि समस्याओं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं और विटामिन की कमी के लिए मुफ्त एलोपैथिक दवाएं प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा, सभी रोगियों को सैनिटरी नैपकिन, कीटाणुनाशक, मास्क और साबुन जैसी स्वच्छता संबंधी वस्तुएं निःशुल्क वितरित की गईं। इस सहयोग का अंतिम लक्ष्य जरूरतमन्द लोगो को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

पहली अगस्त को होगा असंगठित मजदूरों का सम्मेलन

ई श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों को लाभार्थी का दर्जा दे सरकार

संवाददाता

लखनऊ। असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड की 31 जुलाई को हो रही बैठक की बातचीत और निर्णय के आलोक में 1 अगस्त को आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए असंगठित मजदूरों का सम्मेलन डीएलसी कार्यालय लखनऊ में होगा। यह निर्णय असंगठित मजदूरों के साझा मंच की एटक कार्यालय पर हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एटक के जिला अध्यक्ष रामेश्वर यादव और संचालन टीयूसीसी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद पटेल ने किया। बैठक में प्रस्ताव लेकर कहा गया कि प्रदेश में 8.5 करोड़ पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीपीएल श्रेणी की तरह ही लाभार्थी की श्रेणी में शामिल किया जाए। इन श्रमिकों को आवास, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, मृत्यु एवं दुर्घटना बीमा और अंत्येष्टि राशि आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए। बैठक में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21, 39 व 41 के तहत हर नागरिक के गरिमा पूर्ण जीवन की गारंटी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं और उसी के आदेश पर ई श्रम पोर्टल का निर्माण हुआ और देशभर में करोड़ों श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। दुखद यह है कि पंजीकरण के बाद आज तक इन श्रमिकों के लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू नहीं किया गया है। 2008 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून का निर्माण किया गया लेकिन सरकारों ने इसे विफल कर दिया। इस पर प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, यह संकल्प बैठक में लिया गया। बैठक में एटक के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, यूपी वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर, सीआईटीयू के प्रदेश महामंत्री प्रेम नाथ राय, सेवा की फरीदा जलीस, उदय नाथ, नवमी लाल, विकास स्वरूप, स्मिता पांडे, राम सुरेश यादव, रामनाथ मिस्त्री, बृज किशोर यादव, रमेश कश्यप, मोहम्मद अकरम, सीता, मोहम्मद सलीम, चांद बाबू, शुभम शर्मा, अमर सिंह, अमित सिंह आदि लोगों ने अपनी बात रखी।

पीएमजी ने किया डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारंभ

संवाददाता

लखनऊ। डाकघर निर्यात केंद्र से घर बैठे उद्यमियों को विदेशों हेतु पार्सल बुकिंग व कस्टम क्लियरेंस की सुविधा मिलेंगी।बदलते परिवेश में डाक विभाग नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाते हुए नित नवाचार कर रहा है। ई–कॉमर्स के चलन से पार्सल व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पार्सल भेजे जा रहे हैं। पीएमजी वाराणसी कृष्ण कुमार यादव ने विशेश्वरगंज स्थित वाराणसी प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारम्भ किया। अब यहाँ से विभिन्न उद्यमी विदेशों में पार्सल भेज सकेंगे और घर बैठे कस्टम क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले ही दिन वाराणसी के डाकघर निर्यात केंद्र से कुवैत, आयरलैंड और न्यूजीलैंड देशों के लिए बुकिंग की गई। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि शीघ्र ही वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर प्रधान डाकघर, बलिया प्रधान डाकघर, भदोही मुख्य डाकघर एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय उपडाकघर में भी उद्यमियों की सुविधा के लिए डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी।पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि विदेश भेजने हेतु पार्सल बुक करवाने के लिए अब ग्राहकों को डाकघर आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से अपना पार्सल बुक कर सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग द्वारा देश भर के जिला मुख्यालय के प्रधान,मुख्य डाकघरों में डाकघर निर्यात केंद्र खोले जा रहे हैं। सेव के लिए उद्यमियों को भारतीय डाक के पोर्टल www-indiapost-gov-in पर या सीधे https://dnk-cept-gov-in/customers-web/ लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने हेतु उद्यमियों को निर्यातक होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। श्री यादव ने कहा कि ओडीओपी और जीआई उत्पादों की मांग भी विदेशों में दिनों–ब–दिन बढ़ रही हैं ऐसे में डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से इन्हें विदेशों में आसानी से भेजा जा सकेगा।

योगी से मिले राजभर की तारीफ

संवाददाता

लखनऊ। एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश को उन्नति की जिस पथ पर ले गये हैं, वह अभूतपूर्व है। राजभर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, राजग में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, चर्चा के दौरान भर,राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर सहमति। जनकल्याण के मार्ग पर चलते हुए योगी ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की जो ऊंचाइयां दी है, वह निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। योगी से मुलाकात के समय राजभर के दोनों पुत्र अरविंद राजभर और अरुण राजभर भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले राजभर के नेतृत्व वाली सुभासपा रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई। राजभर के राजधानी दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद यह घोषणा की गई। शाह ने एक ट्वीट में कहा था, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़ने का निर्णय लिया है। मैं राजग परिवार में उनका स्वागत करता हूं। सुभासपा प्रमुख 18 जुलाई को दिल्ली में राजग की बैठक में भी शामिल हुए। राजभर ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद वह सपा से अलग हो गए थे। उन्होंने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था।राजभर की पार्टी ने 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। सरकार बनने पर राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने भाजपा नेतृत्व और सरकार पर गंभीर आरोप लगाये थे।

योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

यूपी नीट–यूजी 2023 काउंसिलिंग शेड्यूल जारी

संवाददाता

लखनऊ। यूपी नीट–यूजी 2023 का काउंसिलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में डठठै और ठवै कोर्स में दाखिले के लिए छम्म्ड परीक्षा में सफल अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए 25 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए फीस देनी होगी। यह फीस नॉन–रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन के बाद सीट का आवंटन किया जाएगा। जिसके बाद अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। 8 अगस्त तक हर हाल में अभ्यर्थियों को कॉलेजों में प्रवेश करना होगा। काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को िजजचेरूध्नचदममज.हवअ.पद पर जाकर 2 हजार रुपए फीस ऑनलाईन जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह अमाउंट नॉन रिफंडेबल हैं। काउंसिलिंग में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 30 हजार की सिक्योरिटी मनी यानी धरोहर राशि जमा करनी होगी। वही निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख की धनराशि देनी होगी। चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने सभी डाक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लिया हैं और धरोहर धनराशि या Security Money जमा कर दी हैं।

लखनऊ जिला बैडमिंटन चौम्पियनशिप 21 जुलाई से प्रारम्भ

संवाददाता

लखनऊ। जिला बैडमिंटन चौम्पियनशिप का आयोजन बी0बी0डी0 बैड़मिन्टन आकदमी, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक किया जा रहा है। इस चौम्पियनशिप के पहले व दूसरे चरण में सभी वरीयता खिलाडी तीसरे दौर में पहुचे सभी खिलाडी ने प्रारम्भिक मैच आसानी से जीते इस प्रतियोगिता में लगभग 350 से 400 प्रतिभागी भाग ले रहे है।

जोकि 24 स्पर्धा मे भाग ले रहे है। जिला लखनऊ बैडमिंटन चौम्पियनशिप का उद्घाटन अखिलेश कालरा (एडवोकेट) उपाध्यक्ष यूपी बीए, के द्वारा किया गया। उन्होने अपने उद्बोधन में सभी खिलाड़ियों को आर्शीवाद दिया।

33वीं पुण्य तिथि पर याद किए गए स्व. पं. रामपाल त्रिवेदी

संवाददाता

लखनऊ। आजा जननायक के रूप में अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,पूर्व विधायक एवम् संस्थापक रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज, गोसाईगंज, लखनऊ स्व. पंडित रामपाल त्रिवेदी जी को 33 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर याद किया गया। रामपाल त्रिवेदी सेवा संस्थान के संयोजक स्व. त्रिवेदी जी के प्रपौत्र मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि आज स्व. बाबा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐशबाग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाना था परंतु त्रिवेदी परिवार से जुड़े एक रिश्तेदार के आकस्मिक निधन के चलते उक्त श्रद्धांजलि सभा को स्थगित कर दिया गया। मोहनीश त्रिवेदी ने कहा कि जल्दी ही वह मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज कर कैसरबाग स्थित बाबा जी के नाम से बने हॉल रामपाल प्रशाल जो काफी समय से बंद पड़ा को खुलवाने, हॉल का पुर्निर्माण व वहीं बाबा जी की प्रतिमा लगवाने की मांग रखेंगे वही संस्था के संरक्षक व स्व. त्रिवेदी जी के पुत्र अरुण कुमार त्रिवेदी जी ने स्व. त्रिवेदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि केवल त्रिवेदी परिवार ही नही सम्पूर्ण लखनऊ जिले के लोग आज भी स्व. त्रिवेदी जी व उनके द्वारा किए गए अनेकों महान कार्यों को याद करते हुए उत्साह से भर जाते है व उनके द्वारा कहे गए शब्द संघर्ष ही जीवन है की राह पर चलते हुए आज भी सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन कर रहे है।

योगी ने पूर्व राज्यपाल की पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित

कहा, शून्य से शिखर की यात्रा जैसा रहा लालजी टंडन का जीवन

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे स्व. लालजी टंडन की तीसरी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सीएम हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के सामने आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लालजी टंडन ने लखनऊ में श्रद्धेय अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ''लालजी टंडन ने लखनऊ में अटल जी (अटल बिहारी वाजपेयी) की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनकी स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं। योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा रही। एक सामान्य कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद और बिहार व मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने अनुभव और योग्यता का परिचय देकर जो लाभ प्रदेश और अन्य राज्यों को दिया, वह उल्लेखनीय है और व्यवस्था के लिए एक उदाहरण भी है। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ के साथ उनके आत्मीय संबंध थे, जिन्हें यहां लोग आज भी स्मरण करते हैं। हर जाति, मत, मजहब के लोगों के साथ उनका संवाद, प्यार और सम्मान अद्भुत है। इस अवसर पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित रहे। सभी नेताओं ने भी स्व. लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी।

चार दुकानों के शटर काटकर चोरी,लाखों का सामान लेकर बदमाश फरार

संवाददाता

लखनऊ। गोसाइगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगागंज इलाके में गुरुवार रात चोरों ने चार दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह को हुई। इन चारों दुकानों से लाखों रुपये का सामान चोरी हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।मामला गोसाइगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगागंज चौकी इलाके के भदुवा चौराहे का है। यहां पर देर रात चार दुकानों पर चोरी हुई। ये दुकानें इंजन पार्ट्स, न्यू साइकिल सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक व फुटवियर की थीं। शातिर चोर दुकान का शटर तोड़कर लाखों का माल चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिक जब सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान का शटर टूटा देखकर दंग रह गए। एक लाइन से रहे चारों दुकान के हालत यही रहे। इसके बाद सभी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। साइकिल की दुकान के मालिक अरविंद वर्मा ने बताया कि देर रात दुकान का शटर तोड़ा गया। दुकान में रखी नगदी के साथ सामान भी चोरी किया गया है। फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक वारिश ने बताया कि वह एक हाथ से विकलांग हैं। दुकान के सहारे घर का खर्च चलता है। दुकानदार राजेश तिवारी की इंजन पार्ट्स की दुकान है। उन्होंने भी दुकान में लाखों के नुकसान की बात कही है। इस मामले में गोसाइगंज कोतवाली प्रभारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। चोरी हुए सामान का आंकलन किया जा रहा है। तहरीर मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब दो महीने पहले मलौली पुलिया स्थित किराने की दुकान में भी इसी तरीके से शटर काटकर चोरी की गई थी। जिसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है।

आजाद समाज पार्टी के जंतर मंतर पर धरने के समर्थन में पहुँचे जयंत चौधरी

संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि आज आजाद समाज पार्टी द्वारा दिल्ली के जन्तर मन्तर में आयोजित किये गये विशाल धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह तथा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यूपी के देवबंद में विगत 28 जून को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था।

पर्यटन विभाग का एक लाख पौध रोपण का लक्ष्य

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने वृहद वृक्षारोपण अभियान–2023 हेतु पर्यटन विभाग के लिए एक लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विभागीय अधिकारियो,कर्मचारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी कम से कम एक छायादार फलदार पौधे का रोपण अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 22 जुलाई को 30 करोड़ तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 05 करोड़ पौधों का रोपण किया जायेगा। जयवीर सिंह कल देर शाम पर्यटन भवन में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के सम्बंध में तैयारी बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही उसके देखभाल एवं संरक्षित रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर पीपल, कदम्ब, गुलमोहर, हरसिंगार, अशोक, गुड़हल, बोगन बेलिया तथा अमलताश के अलावा कार्यालयों, आवासीय परिसर, शैक्षिक संस्थानों में आम, महुआ, जामुन, सागौन, शीशम, अमरूद, मौलश्री, नीली गुलमोहर तथा झीलों एवं तालाबों के किनारे बरगद, सावनी, गूलर, लाल कनेर के पौधे रोपित करने के निर्देश दिये।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।